

## BOCW अधिनियम, 1996 से संबंधित नधियों का सीमति उपयोग

### प्रलिम्स के लिये:

[सूचना का अधिकार](#), [अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन](#), [उपकर](#), [मुख्य श्रम आयुक्त](#), प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PM-SBY), आयुष्मान भारत

### मेन्स के लिये:

भारत में वनिरिमाण श्रमिकों का कल्याण, श्रम कानून और उनकी प्रभावशीलता, भारत में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम

[स्रोत: द हट्टि](#)

### चर्चा में क्यों?

[सूचना के अधिकार \(RTI\)](#) से पता चला है कि विभिन्न राज्यों के कल्याण बोर्ड भवन और अन्य सन्नरिमाण कर्मकार (नयोजन तथा सेवा-शर्त वनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत एकत्रित 70,744 करोड़ रुपए के कुल उपकर का उपयोग करने में वफिल रहे हैं।

### BOCW अधिनियम, 1996 क्या है?

- **परचिय:** इसका उद्देश्य भारत में भवन एवं अन्य सन्नरिमाण कर्मकारों के अधिकारों, कल्याण एवं कार्य स्थितियों की सुरक्षा करना है।
  - इसके तहत इनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी उपायों पर ध्यान देने के साथ रोजगार वनियमों को प्रबंधित करना शामिल है जिससे सबसे कमजोर श्रम कषेत्रों में से एक के रूप में इसमें बेहतर कार्य स्थितियाँ सुनिश्चित हो सकें।
  - यह अधिनियम अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के सदिधांतों के अनुसार तैयार (वशिष रूप से वनिरिमाण सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ILO कन्वेंशन संख्या 167 के अनुरूप) कया गया है।
- **प्रमुख वशिषताएँ:**
  - **कल्याणकारी उपाय:** सन्नरिमाण कर्मकारों के कल्याण के लिये राज्य सरकारों को नयिकताओं से 1% से 2% तक उपकर एकत्र करने का अधिकार दया गया है।
  - एकत्रित धनराशिका उद्देश्य स्वास्थ्य, शकिषा एवं सामाजिक सुरक्षा जैसे लाभ प्रदान करना है जिसमें अस्थायी आवास, पेयजल एवं शौचालय शामिल हैं।
  - राज्य/संघ राज्य कषेत्र कल्याण बोर्डों को उपकर नधिका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के क्रम में कल्याणकारी योजनाओं को क्रयान्वति करने हेतु प्रोत्साहति करना।
  - **सुरक्षा प्रावधान:** इस अधिनियम के तहत 500 से अधिक कर्मकारों को रोजगार देने वाली साइटों के लिये आपातकालीनकार्य योजना तैयार करने का प्रावधान कया गया है।
    - **प्रयोज्यता:** यह अधिनियम 10 लाख रुपए से कम लागत वाली नज़ी आवासीय वनिरिमाण परयोजनाओं को छोड़कर, 10 या अधिक नरिमाण श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतषिठानों पर लागू होता है।
      - नयिकताओं को इस अधिनियम के लागू होने के 60 दनों के भीतर अपने प्रतषिठानों को इसके अंतर्गत पंजीकृत कराना अनविर्य है।
  - **प्रवरतन तंत्र:** मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और उसके कषेत्रीय कार्यालय अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हैं तथा सुरक्षा और कल्याण उपायों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये नधिमति नरीक्षण करते हैं।
  - इसके अतरिकित, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश BOCW कल्याण बोर्ड कल्याणकारी योजनाओं को क्रयान्वति करते हैं और अधिनियम के तहत एकत्रित उपकर नधिका उपयोग करते हैं।

**नोट:** वर्ष 1988 में अपनाए गए ILO कन्वेंशन संख्या 167 (भारत द्वारा अनुसमर्थित) का उद्देश्य नरिमाण स्थलों पर कार्य स्थितियों में सुधार हेतु मानक स्थापति करके वनिरिमाण उद्योग में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है।

## BOCW अधिनियम, 1996 के संबंध में चर्चाएँ क्या हैं?

- एकत्रित उपकर का न्यूनतम उपयोग: एक प्रमुख चर्चा एकत्रित उपकर में 70,744 करोड़ रुपए का न्यूनतम उपयोग है, जो एकत्रित की गई धनराशि और श्रमिकों को आवंटित लाभ के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है।
  - महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने उपकर से क्रमशः 13,683.18 करोड़ रुपए, 7,921.42 करोड़ रुपए और 7,826.66 करोड़ रुपए खर्च किये, जिससे क्रमशः 9,731.83 करोड़ रुपए, 7,547.23 करोड़ रुपए और 6,506.04 करोड़ रुपए शेष रह गए।
    - इन राज्यों में उपकर का अधिशेष, श्रमिकों के कल्याण के लिये नधियों का उपयोग करने की उनकी प्रतिबद्धता के बारे में चर्चा उत्पन्न करता है।
  - केरल को छोड़कर, अधिकांश राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनिक भवन एवं अन्य वननिर्माण श्रमिक अधिनियम को लागू नहीं कर रहे हैं।
- उपकर चोरी और गलत रिपोर्टिंग: नियोक्ताओं और बलिडरों द्वारा बड़े पैमाने पर उपकर चोरी के बारे में चर्चाएँ बनी हुई हैं, महाराष्ट्र का उपकर संग्रह इसकी वननिर्माण गतिविधि के साथ असंगत प्रतीत होता है।
  - इसके अतिरिक्त, स्वीकृत वननिर्माण परियोजनाओं की वास्तविक लागत के विवरण में पारदर्शिता का अभाव है।
- वलिंबित कल्याणकारी उपाय: श्रमिकों के आवास, जल और स्वच्छता के लिये अधिनियम के प्रावधानों को अनुचित तरीके से लागू किया गया, विशेष रूप से कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, जिससे श्रमिकों को सहायता के बिना रहना पड़ा।
  - इसके अतिरिक्त, संकट के दौरान वित्तीय सहायता समेत वादा किये गए कल्याणकारी लाभ अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जो अधिनियम की अप्रभावीता को उजागर करता है।
- कार्यान्वयन संबंधी चर्चाएँ: केरल को छोड़कर, अधिकांश राज्य और केंद्रशासित प्रदेश BOCW अधिनियम, 1996 को लागू नहीं कर रहे हैं, जिससे निर्धारित लाभ सीमित हो रहे हैं।
  - कई राज्य कल्याणकारी बोर्डों का पुनर्गठन करने से बच रहे हैं, जिससे ऐसी चर्चाएँ बनी हैं कि कल्याणकारी योजनाओं की अप्रयुक्त धनराशि राज्य के खजाने में चली जाएगी।
- सामाजिक सुरक्षा पर संहति का प्रभाव: प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा संहति (CSS), 2020 उपकर संग्रह को कम कर सकती है, क्योंकि यह नियोक्ताओं को उपकर का स्व-मूल्यांकन करने की अनुमति देती है और उपकर की दर तथा ब्याज को कम करती है।
  - इससे श्रमिकों के अधिकार भी सीमित हो जाते हैं, तथा आवास जैसे आवश्यक लाभ गारंटीकृत होने के बजाय वैकल्पिक हो जाते हैं।

## नरिमाण श्रमिकों से संबंधित अन्य योजनाएँ

- [नरिमाण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल \(NIPUN\)](#)
- [प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन \(PM-SYM\)](#)
- [प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना \(PM-SBY\)](#)
- [आयुष्मान भारत](#)
- [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005](#)
- [ई-श्रम](#)

## आगे की राह

- **उन्नत नगरानी:** उपकर नधियों के उपयोग पर नज़र रखने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सतत अंकेक्षण और पारदर्शी रिपोर्टिंग तंत्र का कार्यान्वयन किया जाना चाहिये।
  - उपकर संग्रह, आवंटन और उपयोग पर नज़र रखने के लिये ई-श्रम जैसी पहलों के माध्यम से श्रमिकों के लिये रियल टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किये जाने चाहिये।
- **राज्य सरकार की जवाबदेही:** BOCW अधिनियम, 1996 के उचित कार्यान्वयन और उपकर नधियों के प्रभावी उपयोग के लिये राज्यों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
  - प्रभावी रूप से धन का उपयोग करने वाले राज्यों को प्राथमिकता देते हुए और नमिन प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिये अतिरिक्त धन आवंटन को अवधारित किये जाने के साथ नधिप्रादान-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिये।
- **CSS 2020 की समीक्षा:** प्रस्तावित CSS, 2020 को स्वास्थ्य कवरेज जैसे अनविर्य श्रमिक अधिकारों को बनाए रखने के लिये संशोधित किया जाना चाहिये।
- **श्रमिक शिक्षा और जागरूकता:** कॉर्पोरेट और नरिमाण कंपनियों को BOCW अधिनियम के तहत श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और बेहतर सुरक्षा और पारिश्रमिक के लिये गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के साथ सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिये।

?????? ???? ?????:

**प्रश्न.** श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार तथा सेवा-शर्त वनियमन) अधिनियम, 1996 की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????:**

प्रश्न. प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका नभाने वाली 'श्रेणी' संगठन के संदर्भ में, नमिनलखिति में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2012)

1. प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधकिरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था ।
2. 'श्रेणी' ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चति करती थी ।
3. श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था ।

नमिनलखिति कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

**??????:**

प्रश्न. अंगरेजों द्वारा भारत से अन्य उपनिवेशों में गरिमटिया मज़दूरों को क्यों ले जाया गया? क्या वे वहाँ अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में सक्षम रहे हैं? (2018)

प्रश्न. पछिले चार दशकों में भारत के भीतर और बाहर श्रम प्रवास की प्रवृत्तियों में आए बदलावों पर चर्चा कीजिये । (2015)